प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय

(चालू मूल्यों पर रुपयों में)

	ग्रामीण		शहरी	
	1983-84	1987-88	1983-84	1987-88
गरीब	62.27	84.17	74.98	100.25
अमीर	146.23	195.18	201.29	288.46
गरीब के मुकाबले अमीर का उपभोग व्यय अनुपात	2.35	2.32	2.88	2.88

(घ) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विकास स्कीम और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जीवन के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। गरीब लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों, अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) आवश्यक वस्तुओं में मूल्यवृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करके 1700 जनजातीय पहाड़ी पिछड़े ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका में विस्तार किया गया है। सरकार ने मूल्यवृद्धि को रोकने और इनकी पूर्ति में वृद्धि करने के लिए गेहूं और खाद्य तेलों का आयात भी किया है।

(च) 30 आवश्यक वस्तुओं में से 11 आवश्यक मदों के मूल्य में इस वर्ष मार्च के अंत की तुलना में नवम्बर, 1992 में वस्तुतः गिरावट आई है। कुल गिरावट गेहूं में 4.1 प्रतिशत, ज्वार में 3.1 प्रतिशत और बाजरे के मामले में 26.7 प्रतिशत रही है। अन्य आवश्यक वस्तुओं में यह गिरावटः अरहर में 5.0 प्रतिशत, मूंग में 10.4 प्रतिशत, उड़द में 3.4 प्रतिशत, सरसों के तेल में 4.3 प्रतिशत, मूंगफली के तेल में 4.3 प्रतिशत, वनस्पति तेल में 0.6 प्रतिशत, नमक में 2.7 प्रतिशत और लट्ठे में 2.5 प्रतिशत रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल मिलाकर खाद्यान्न मूल्यों में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष मध्य-नवम्बर तक इनमें 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी।

Clearance of Haldia Petrochemical Project by the IDBI

*306. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRIMATI SARALA MAHESHWARI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the proposed Haldia Petrochemical Project is pending before the Appraisal Committee of the IDBI since a long time; and

(b) if so, by when the IDBI will take a decision on the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) It has been reported by the Industrial Development Bank of India (IDBI) that the project proposal of Haldia Petrochemical Ltd. (HPL) which was formulated in 1990-91 was supported by the financial institutions in June, 1991. In view of the changed economic scenario, HPL changed the project scope and approached financial institutions for reconfirmation of their assistance in April, 1992. The Company's request was considered at a Joint Institutional Meeting held in September, 1992 pursuant to which a committee has been constituted to look into various aspects of the viability of the reformulated project proposal with the help of two outside experts selected in consultation with the company.

(b) IDBI will take a decision only after the Committee has finalised its report.